साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 10, अंक : 28 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 12 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

2050 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए तकनीकी विकास पर्याप्त नहीं

नई दिल्ली। मॉडल दिखाता है कि नवीकरणीय स्त्रोतों से 100 फीसदी बिजली उत्पादन हासिल करना एक जरूरी कदम है, लेकिन खाद्य उत्पादन जैसी अन्य क्षेत्रों को भी तुरंत हल किया जाना चाहिए। तकनीकी और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश के बावजूद, जनसंख्या में वृद्धि और साथ ही बढ़ती व्यक्तिगत खपत हो सकता है कटौती की भरपाई न कर पाएं, जिससे देश अपने 2050 के लक्ष्यों को पूरा करने से चूक जाएंगे।

अधिकांश देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी प्रगति और बुनियादी ढांचे में बदलाव पर निर्भर हैं। हालांकि पर्यावरण शोधकर्ताओं के बेन-गुरियन विश्वविद्यालय के एक नए मॉडल से पता चलता है कि यह पर्याप्त नहीं होगा और इसके पीछे के और अधिक कारणों पर विचार किया जाना चाहिए। शोध के अनुसार, दुनिया भर में बढ़ती आबादी और उनकी बढ़ती खपत से इशारा मिलता है कि तकनीकी और बुनियादी ढांचे में बदलाव नाकाफी हैं। तकनीकी और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश के बावजूद, जनसंख्या में वृद्धि और साथ ही बढ़ती व्यक्तिगत खपत हो सकता है कटौती की भरपाई न कर पाएं, जिससे देश अपने 2050 के लक्ष्यों को पूरा करने से चूक जाएंगे। दुनिया भर 2050 तक जनसंख्या में 20 फीसदी तक की वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है। इजराइल एक विशेष रूप से दिलचस्प केस स्टडी है क्योंकि देश में जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है। हालांकि यह मॉडल सभी देशों पर लागू होता है। तकनीकी और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश के बावजूद, जनसंख्या में वृद्धि और साथ ही बढ़ती व्यक्तिगत खपत हो सकता है कटौती की भरपाई न कर पाएं, जिससे देश अपने 2050 के लक्ष्यों को पूरा करने से चूक जाएंगे। मॉडल ने जनसंख्या वृद्धि, इजराइल में व्यक्तिगत उपभोग की आदतों में बदलाव और बिजली, यातायात, पानी, भोजन और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संबंधित उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीकी विकास के कार्यान्वयन के अपेक्षित प्रभावों की जांच-पड़ताल की। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि तकनीकी और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के बावजूद, स्वीकृत कदमों से प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में 65 फीसदी की कमी आने की उम्मीद है, लेकिन निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण, इजराइल का कार्बन पदचिह्न केवल 33 फीसदी कम होगा जबकि पानी और भूमि उपयोग में वृद्धि होगी। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि तकनीक और बुनियादी ढांचे में बहुत अधिक उपलब्धियों के बावजूद, अपेक्षित जनसंख्या वृद्धि और व्यक्तिगत खपत में वृद्धि उत्सर्जन में कमी को बेअसर कर सकती है। मॉडल दिखाता है कि नवीकरणीय स्त्रोतों से 100 फीसदी बिजली उत्पादन हासिल करना एक जरूरी कदम है, लेकिन खाद्य उत्पादन जैसी अन्य क्षेत्रों को भी तुरंत हल किया जाना चाहिए।

तकनीकी और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश के बावजूद, जनसंख्या में वृद्धि और साथ ही बढ़ती व्यक्तिगत खपत हो सकता है कटौती की भरपाई न कर पाएं, जिससे देश अपने 2050 के लक्ष्यों को पूरा करने से चूक जाएंगे।

इसके अलावा मॉडल से पता चलता है कि जनसांख्यिकीय प्रक्रियाएं इस युग में विदेशों से खाद्य आयात पर इजराइल की निर्भरता को बढ़ाएंगी जब अधिकांश भोजन पहले से ही बाहरी स्त्रोतों से आता है और दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा के बावजूद, जो अन्य चीजों के अलावा जलवायु संकट के कारण बढ़ रही है। ये परिणाम नए तरीके से खेती करने की जरूरत पर जोर देते हैं जो उत्सर्जन को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेंगे, ऐसे लक्ष्य जिन्हें इजराइल ने अतीत में हासिल किया है। यह शोध नेचर सस्टेनेबिलिटी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

महाकुंभ में मुख्यमंत्री यादव ने लगाई आस्था की डुबकी

प्रयागराज । मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार को प्रयागराज महाकुंभ में सपरिवार शामिल होने पहुंचे। त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई और दर्शन पूजन किया। स्नान करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मां गंगा और मां यमुना के संगम का किनारा है। तीर्थराज प्रयाग में स्नान का जो आनंद है वो कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वासियों के जीवन में खुशहाली आए, सभी का मंगल और कल्याण हो आज इसी भावना के साथ मैं इस महाकुंभ में शामिल हुआ।

दलदली भूमि से मीथेन उत्सर्जन में हो रही है भारी बढ़ोतरी- अध्ययन

शिमला। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि हवा में सल्फर की मात्रा कम करने से अनजाने में पीटलैंड, वेटलैंड या दलदल जैसी जमीन से मीथेन का प्राकृतिक उत्सर्जन बढ़ गया है।

शोध से पता चलता है कि स्वच्छ वायु नीतियों के कारण दुनिया भर में सल्फर उत्सर्जन में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बढ़ते तापमान के प्रभावों के साथ मिलकर दलदल वाली जमीन मीथेन उत्पादन पर अंकुश नहीं लगा पाई, जिसके कारण उत्सर्जन में वृद्धि होती दिखाई दे रही है।

शोध के मुताबिक, प्राकृतिक आर्द्रभूमि से हर साल दो करोड़ से 3.5 करोड़ मीट्रिक टन अतिरिक्त मीथेन उत्सर्जित हो रही है। जिसका मतलब है कि मानवजनित उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य दुनिया भर में मीथेन संकल्प में वर्तमान में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कड़े होने चाहिए। मीथेन, जो वायुमंडल में गर्मी को फंसाने वाली सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों में से एक है, दुनिया भर की आर्द्रभूमि में उत्पन्न होती है। सल्फर का प्राकृतिक आर्द्रभूमि पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है जो मीथेन उत्सर्जन को कम करता है, जबकि सीओ2 मीथेन-उत्पादक सूक्ष्मजीवों के लिए भोजन बनाने वाले पौधों में वृद्धि करके मीथेन उत्पादन को बढ़ाता है। जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया कि वायुमंडलीय सल्फर को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई अच्छी नीतियों का अप्रत्याशित परिणाम यह हुआ है कि आर्द्रभूमि मीथेन उत्पादन पर सल्फर का %ढक्कन% हट गया है। बढ़ी हुई सीओ2 का मतलब है कि हम पर दोहरा प्रभाव पड़ता है जो उत्सर्जन को बहुत अधिक बढ़ा देता है। शोध के मुताबिक, यह कैसे हुआ? सल्फर बैक्टीरिया के एक समूह को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है जिससे वे मीथेन का उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीवों के दूसरे समूह को मात दे सकते हैं, जब वे आर्द्रभूमि में उपलब्ध सीमित भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। पिछली शताब्दी के दौरान अम्लीय बारिश सल्फर प्रदूषण की स्थितियों में, यह आर्द्रभूमि मीथेन उत्सर्जन को आठ फीसदी तक कम करने के लिए पर्याप्त था।

दलदली भूमि से मीथेन उत्सर्जन में हो रही है भारी बढ़ोतरी- अध्ययन

अब जबकि स्वच्छ वायु नीतियां शुरू की गई हैं, सल्फर जमाव को कम करने का बुरा परिणाम, जिसका विश्व के पारिस्थितिकी तंत्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पेरिस समझौते में निर्धारित सुरक्षित जलवायु सीमाओं के भीतर रहने के लिए जितना सोचा गया था, उससे कहीं अधिक मेहनत करनी होगी।

ग्लासगो में कॉप26 में 150 से अधिक देशों ने दुनिया भर में मीथेन संकल्प पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य 2020 के आधार रेखा पर 2030 तक मीथेन के मानवजनित उत्सर्जन को 30 फीसदी तक कम करना है।

यह अध्ययन वायुमंडलीय सल्फर में कमी को अनुमानित दर से अधिक तेजी से तापमान वृद्धि में शामिल करने वाला नया अध्ययन है। 2020 में, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड और महीन कणों के उत्सर्जन को कम करने के लिए शिपिंग प्रदूषण नियंत्रण शुरू किए गए थे। महासागरों पर वायुमंडलीय सल्फर में यह कमी अपेक्षा से अधिक तापमान वृद्धि में शामिल है जिसे %टर्मिनेशन शॉक% के रूप में जाना जाता है।

शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया कि अध्ययन जलवायु प्रणाली की जटिलता की ओर इशारा करता है। इन जटिल जैव-रासायनिक आंतरिक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व पहले भविष्य के मीथेन उत्सर्जन के अनुमानों में अच्छी तरह से शामिल नहीं किया गया है।

शोध में कहा गया है कि इस भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैस के संभावित भविष्य की सही समझ हासिल करने के लिए इन सुझावों पर विचार करना जरूरी है।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला- 2025 में मध्यप्रदेश की पुस्तकें बनीं आकर्षण का केंद्र

भोपाल नई दिल्ली के भारत मंडपम में 9 फरवरी तक चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले- 2025 में मध्यप्रदेश की पुस्तकें खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेले में हॉल नंबर 2 के आर-59 में शासन के पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग का संयुक्त स्टॉल तथा पी-06 में मप्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का स्टॉल लगाया गया है।

पर्यटन और संस्कृति विभाग के स्टाल में भोपाल और उज्जैन के प्रतिष्ठित प्रकाशकों जैसे स्वराज संस्थान, धर्मपाल शोधपीठ, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, वीर भारत न्यास, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास तथा हिन्दी साहित्य अकादमी की पुस्तकें विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से राज्य के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, कला-संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहर और पुरातत्व जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाएं भी यहां उपलब्ध हैं। गांधी दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन, लोकगीत तथा देवी-स्तुति गीत, भित्ति चित्र, लोक तथा जनजातीय कला जैसे विषयों पर आधारित दुर्लभ पुस्तकों को पाठक खूब पसंद कर रहे हैं।

बजट 2025-26 स्कूली छात्रों की नजर में

नई दिल्ली, केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओबेदुल्लागंज के कक्षा 11 के छात्रों अनंता बरैया, उदय पचौरी, शिव कुमार, रमनप्रीत कौर और अनन्या तिवारी ने भी इसे प्रिंसिपल ललिता मैम, वैभव सर, कृष्णा मैडम के मार्गदर्शन में बजट का अध्ययन कर अपनी दृष्टि से प्रमुख बिंदुओं को उजागर किया है। छात्रों ने बजट को खासतौर पर शिक्षा, रोजगार, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य और कृषि के नजरिए से देखा और बताया कि यह आने वाले वर्षों में उनके करियर और जीवन को कैसे प्रभावित करेगा।

बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताएँ (छात्रों के अनुसार)

शिक्षा और कौशल विकास

बजट में मेडिकल और इंजीनियरिंग की 82,000 नई सीटों की घोषणा को छात्रों ने एक सकारात्मक कदम बताया। इसके अलावा, ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋ्रण और तकनीकी एवं अनुसंधान क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्तियाँ युवाओं के लिए उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाएंगी। छात्रों ने डिजिटल लर्निंग संसाधनों के विस्तार का स्वागत किया लेकिन यह भी सुझाव दिया कि देश के हर गाँव और छोटे शहर में इंटरनेट की सुगमता और डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

रोजगार और स्टार्टअप्स

सरकार द्वारा पाँच वर्षों में तीन करोड़ नौकरियाँ सृजित करने के लक्ष्य को छात्रों ने एक सराहनीय कदम बताया। ?10,000 करोड़ के स्टार्टअप फंड को उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना गया जो भविष्य में अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, गिग वर्कर्स (फ्रीलांसर्स) के लिए सरकार द्वारा पहचान पत्र जारी करने और एक ई-पोर्टल लॉन्च करने को भी सकारात्मक पहल माना गया।

कृषि और पर्यावरण संरक्षण

छात्रों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर सरकार के जोर की सराहना की। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसानों को जागरूक करने के लिए स्कूल स्तर पर कृषि और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम होने चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाएँ और डिजिटल इंडिया

बजट में हर जिले में कैंसर उपचार केंद्रों की स्थापना और बुजुर्गों के लिए ?1 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋ्रण को लेकर छात्रों ने अपनी राय व्यक्त की। इसके अलावा,ढ्ढ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि भविष्य में डिजिटल इंडिया की दिशा में छात्र पहले से ही तैयार हो सकें।

बजट के लाभ और चुनौतियाँ- छात्रों की दृष्टि से

फायदे-

-उच्च शिक्षा के अवसरों में वृद्धि

-स्टार्टअप्स और नई नौकरियों के लिए बेहतर माहौल

-डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार

-स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, विशेषकर कैंसर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए

चुनौतियाँ-

-ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लर्निंग संसाधनों की कमी

-किसानों के लिए स्स्क(न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर स्पष्ट नीति न होना

-साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सुरक्षा पर अपेक्षित ध्यान न दिया जाना

छात्रों की राय- भविष्य के लिए सुझाव

छात्रों ने सुझाव दिया कि शिक्षा में ढ्ढ और साइबर सुरक्षा को शामिल किया जाए, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक जानकारी दी जाए, और डिजिटल लर्निंग को हर छात्र के लिए सुलभ बनाया जाए।

ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों द्वारा किए गए इस विश्लेषण ने दिखाया कि युवा पीढ़ी न केवल देश की आर्थिक नीतियों को समझ रही है, बल्कि उनके प्रभाव पर अपनी स्पष्ट राय भी रख रही है। यदि सरकार इन पहलों को सही दिशा में लागू करती है, तो यह बजट आने वाले वर्षों में छात्रों और युवाओं के भविष्य को मजबूती से आकार दे सकता है।

2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान-4

नई दिल्ली । भारत ने चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान मिशन 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के जरिये चंद्रमा की चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 में उच्च क्षमता के एलवीएम 3 रॉकेट दो अलग-अलग प्रक्षेपण के बाद पांच अलग-अलग घटकों को लेकर कक्षा में जाएंगे। इनको पृथ्वी की कक्षा में इकट्ठा किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से नमूने इकट्ठे करके उनको पृथ्वी पर वापस लाना है। गगनयान मिशन को अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष यान से अंतरिक्ष की पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2026 में भारत समुद्रयान का भी प्रक्षेपण करेगा। इसमें समुद्र तल में खोज करने के लिए तीन वैज्ञानिक एक पनडुब्बी के जरिये छह हजार मीटर की गहराई में जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि गगनयान अंतरिक्ष मिशन सहित भारत के ऐतिहासिक मिशनों की समयसीमा को तय करेगी। पीएम मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में समुद्रयान मिशन के बारे में बताया था।

टिहरी झील में तैरते होटल की जांच करेगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

टिहरी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 10 फरवरी, 2025 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से टिहरी झील में तैरते होटल और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। गौरतलब है कि इस मामले में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 14 जून 2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर एक विविध आवेदन पंजीकृत किया गया। इस रिपोर्ट को एनजीटी द्वारा 12 फरवरी, 2024 को दिए आदेश के बाद प्रस्तुत किया गया था।

इस मामले को 7 जनवरी, 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर के आधार पर एनजीटी ने स्वत: संज्ञान में लिया है। यह मामला टिहरी झील में तैरते होटल पर केंद्रित है, जो लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद अभी भी चल रहा है। आरोप है कि इसकी वजह से गंगा दूषित हो रही है। 12 फरवरी, 2024 को एनजीटी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से यह जांच करने को कहा है कि क्या तैरते हुए होटल को गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) आदेश, 2016 के तहत अनुमति दी गई थी। साथ ही अदालत ने आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। 14 जून, 2024 की अपनी रिपोर्ट में एनएमसीजी ने स्वीकार किया है कि झील या जल निकाय में तैरते होटलों को गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) आदेश, 2016 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि, रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि क्या एनएमसीजी ने खुद कोई कार्रवाई शुरू की है। वहीं एनजीटी ने 12 फरवरी, 2025 के आदेश में कहा था कि यदि एनएमसीजी को कार्रवाई से रोकने वाला कोई कानूनी मुद्दा या अदालती आदेश नहीं है, तो एनएमसीजी को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2016 के आदेश का पालन किया जाए। वहीं एनएमसीजी को ओर से पेश वकील ने इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए और समय मांगा है। एनजीटी ने इस अनुरोध पर सहमति जताते हुए अगली सुनवाई एक मई, 2025 के लिए निर्धारित की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से छह महीने के भीतर एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। 10 फरवरी, 2025 को दिए इस निर्देश के मुताबिक रिपोर्ट में दो अवैध ईंट भट्टों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) वसूली की स्थिति शामिल होनी चाहिए। साथ ही यूपीपीसीबी अधिकारियों द्वारा दोबारा निरीक्षण के बाद पाए गए भट्टों की स्थिति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में छह महीनों के भीतर नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 22 जून, 2024 को दायर रिपोर्ट के आधार पर एक विविध आवेदन पंजीकृत किया गया था। यह रिपोर्ट एनजीटी द्वारा 12 फरवरी, 2024 को दिए आदेश पर सबमिट की गई है। इस मामले में आवेदक ने अवैध रूप से चल रहे दो ईंट भट्टों को लेकर शिकायत की थी। इनमें से एक देवरिया के पासनपुर गांव में एवीटी ईएनटी उद्योग चकबंदी, और दूसरा देवरिया के गोबराई गांव में मौजूद पीएमटी ईएनटी भट्टा है। संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि दोनों ईंट भट्टे बंद कर दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, अदालत ने 12 फरवरी, 2024 को इस मामले को बंद कर दिया और यूपीपीसीबी को पिछले उल्लंघनों के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने का निर्देश दिया था। वहीं यूपीपीसीबी द्वारा 22 जून 2024 को सबमिट रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने 12 दिसंबर 2023 को दोनों ईंट भट्टों का निरीक्षण किया था। इस दौरान यह दोनों भट्ठे बंद पाए गए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, यूपीपीसीबी ने 31 मई 2024 के आदेशों में एवीटी ईएनटी उद्योग पर 15,75,000 रुपए और पीएमटी ईएनटी भट्टा पर 14,62,500 रुपए का पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाया था। अदालत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट में आदेश पारित होने के बाद पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) वसूलने के लिए की गई किसी कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। यूपीपीसीबी के वकील ने कहा है कि मुआवजा राशि की वसूली शुरू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह जांचने के लिए एक नया निरीक्षण किया जाएगा कि क्या दोनों भट्टे अभी भी बंद हैं या अवैध रूप से फिर से चालू हो गए हैं।

भोपाल में बनेगा संत शिरोमणि विद्यासागर जी का स्मृति स्थल- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की स्मृति में भोपाल में स्मृति स्थल विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर विधानसभा परिसर में आयोजित गुरु गुणानुवाद सभा में गुरु वंदना कर अतिशय पुण्य अर्जित करने पधारे समर्पित भक्तों का राज्य शासन की ओर से अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में सभी आवश्यक नियमों का पालन किया। संत परंपरा का अनुसरण करते हुए उनके प्रकृति के साथ संबंध, जीवन शैली, मानव सेवा और समाज को मार्गदर्शन के माध्यम से वे अपने जीवन काल में ही देवता के रूप में स्वीकारे जाने लगे। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, सेवा, समर्पण जैसे शब्द उनके व्यक्तित्व के सम्मुख छोटे पड़ जाते हैं।

कार्यक्रम में सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक श्री भगवानदास सबनानी, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी. सिंह, जनप्रतिनिधि श्री राहुल कोठारी तथा जैन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिगम्बर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं ने मुकुट तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन किया। उनको शॉल भी सम्मानपूर्वक भेंट की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्जवलित किया तथा मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन और कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्हें नेमावर में संत-श्री के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साक्षात देवता के दर्शन के समान प्रतीत होता संत-श्री का अलौकिक व्यक्तित्व जीवन को धन्य करने वाला था। जैन और सनातन दर्शन में आत्मा की भूमिका आवागमन की बताई गई है। यह माना जाता है कि वस्त्र बदलने के समान ही पवित्र आत्मा शरीर बदलती है। इस दृष्टि से यह मानना कि महाराज जी हमारे बीच नहीं है, व्यर्थ है। वास्तविकता यह है कि उन्हें स्मरण करने और मन की आंखों से देखने के क्षणिक प्रयास मात्र से ही आचार्य श्री विद्यासागर जी के आस-पास होने की सहज अनुभूति होती है। उनके व्यवहार, स्वरूप और विचार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति उन्हें अपना मानते थे। प्रदेशवासियों में संत-श्री के प्रति इतने अपनत्व और आदर का भाव था कि यह किसी को अनुभूति ही नहीं होती थी कि वे कर्नाटक से हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अपनी इच्छा शक्ति से जीवन के कई क्षेत्रों में समाज को दिशा दी। स्वरोजगार के क्षेत्र में जेल से लेकर समाज में महिलाओं को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त किया। गौ-माता की भी उन्होंने चिंता की तथा गौ-माता के माध्यम से लोगों के जीवन और प्रकृति में बदलाव के लिए गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में की गई उनकी पहल अनुकरणीय है। आचार्यश्री ने अपने विचार, भाव और कर्म से समाज को प्रकृति व परमात्मा के समान पुष्पित-पल्लवित, प्रेरित करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संत-श्री का विचार था कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। वे भाषाओं की समृद्धि पर विशेष ध्यान देते थे, उनका विचार था कि भाषाओं की विविधता की जानकारी से भारत की आंतरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है और ज्ञान के लिए भाषाओं की समृद्धि आवश्यक है। गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रदेश में निरंतर प्रयास जारी हैं, इस क्रम में 55 एक्सीलेंस कॉलेज आरंभ किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के अनुसार भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें, नई शिक्षा नीति का आधार है। इसी का परिणाम है की नई शिक्षा नीति में जैन दर्शन सहित भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी विचारों को शामिल किया गया है। प्रदेश में खुले में मांस की दुकानों को भी बंद किया गया। तेज ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। प्रदेश में शराब बंदी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू की गई।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008